

राजस्थान सरकार  
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/ 3252

जयपुर, दिनांक 24.8.2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न प्रारम्भिक कार्य करने बाबत ।

प्रसंग : आयोग का पत्र क्रमांक 23/2016-ईआरएस/वॉल्यूमा दिनांक 12 अगस्त, 2016 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.08.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 01.10.2016 (शनिवार) को किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी, 2017 (मंगलवार) को किया जायेगा।

2. संदर्भ तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की तिथियाँ निम्न प्रकार से है :-

1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	01 अक्टूबर, 2016 (शनिवार)	
2.	दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि	01 अक्टूबर, 2016 (शनिवार) से 31 अक्टूबर, 2016 (सोमवार)	से
3.	मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना	07 अक्टूबर, 2016 (शुक्रवार) 14 अक्टूबर, 2016 (शुक्रवार)	एवं
4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियाँ	16 अक्टूबर, 2016 (रविवार) एवं 23 अक्टूबर, 2016 (रविवार)	
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	30 नवम्बर, 2016 (बुधवार) तक	
6.	डेटाबेस अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	24 दिसम्बर, 2016 (शनिवार) तक	
7.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	10 जनवरी, 2017 (मंगलवार)	

3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु अभियान-2016 के अन्तर्गत ECI-NET पर विभिन्न कार्य यथा – फोटो मैचिंग, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का सत्यापन कर आदिनांक करना, बीएलओ, सुपरवाईजर्स की सूची को अद्यतन करना, मृत/स्थानान्तरित दोहरी प्रविष्टि वाले, मतदाताओं की सूचियों से संबंधित सूचनाओं को आदिनांक करना, मतदान केन्द्रों से संबंधित विभिन्न फॉरमेट में नक्शे CAD Drawing (Polling Station & Key Plan) तैयार कर अपलोड करना, मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण आदि के कार्य किये जा रहे हैं।

इस विषय में दिनांक 16.08.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि उक्त सभी कार्य 31 अगस्त, 2016 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें। कृपया तदनुसार निर्धारित तिथि तक सभी कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. प्रारूप मतदाता सूची 2017 की तैयारी –

इस विषय में जैसा कि आपको विदित है कि संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के साथ मूल मतदाता सूची, 2014 एवं इसके पश्चात् निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में लोकसभा आम चुनाव, 2014 से पूर्व तैयार पूरक सूचियाँ तथा इसके बाद आयोजित किए गए विभिन्न पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तैयार की गयी 6 पूरक सूचियाँ संलग्न है। दिनांक 11 जनवरी, 2016 के बाद वर्तमान में निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान तैयार की गयी पूरक सूची-7 जिसमें कि दिनांक 12.08.2016 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं तत्पश्चात् ERMS अपलोड करने की तिथि तक जो पूरक सूची-7 तैयार की गयी है वह संलग्न है। आयोग द्वारा प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से पूर्व प्रारूप मतदाता सूची, 2017 की तैयारी के विषय में निम्न प्रकार कार्यवाही की जानी है –

- 4.1 पूरक सूची-7 का प्रिन्ट प्राप्त करना– संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2016 तक मतदाता सूची में नाम जुड़ने, संशोधन एवं विलोपन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 12 अगस्त, 2016 तक किया गया था। इस प्रकार सत्त अद्यतन के दौरान निस्तारित आवेदन पत्रों से पूरक सूची 7 का प्रिन्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें तथा दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के साथ इसे रिकार्ड हेतु पूरक सूची-7 का प्रिन्ट गूगल ड्राइव पर "Application Software" के अंतर्गत

**Integration & Roll Monitoring 2.1** पर क्लिक कर लिया जा सकता है।

प्रिन्ट मय फोटो व बिना फोटो दोनों के प्राप्त किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

- 4.2 **एकीकृत मतदाता सूची, 2017** – जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में प्रारूप मतदाता सूची का दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशन किया जायेगा। इसलिए आयोग के निर्देशानुसार इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मूल मतदाता सूची के साथ कोई भी पूरक मतदाता सूचियां संलग्न नहीं की जाएगी अर्थात् सभी पूरक सूचियाँ मूल मतदाता सूची 2014 में एकीकृत की जाकर प्रारूप मतदाता सूची-2017 तैयार की जाएगी। मतदाता सूची के एकीकरण तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य विभाग के SLA मै0 रील द्वारा किया जा रहा है। प्रारूप मतदाता सूची की प्रथम चैकलिस्ट इस माह के अन्त तक ERMS के माध्यम से सभी जिलों को उपलब्ध करवा दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि ERMS पर SLA द्वारा उपलब्ध करवायी गयी उक्त प्रारूप मतदाता सूची 2017 की चैकलिस्ट जिले की अनुबंधित फर्म को उपलब्ध करवाये, ताकि उक्त फर्म द्वारा एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट का प्रिन्ट लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जॉच हेतु उपलब्ध कराया जा सके। यह कार्य आवश्यक रूप से माह सितम्बर, 2016 के प्रथम सप्ताह तक कर लिया जाए। विभाग द्वारा इस प्रारूप मतदाता सूची की चैक लिस्ट की जॉच हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं, जिसके अनुसार चैक लिस्ट की सघन जॉच करवाकर इसमें पायी गयी त्रुटियों को दूर किया जाकर विशुद्ध प्रारूप मतदाता सूची 2017 का मुद्रण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण अभियान के दौरान त्रुटियाँ ERMS के माध्यम से ठीक नहीं करवाई गई हो तो इसे चैक लिस्ट में यथा स्थान संशोधन कर ठीक करवाया जा सकता है।

5. **पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों की आपूर्ति** – मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आवेदन पत्र यथा 6, 7, 8, 8 क, 6(ए), फार्म नम्बर 9, 10, 11, 11ए आदि का मुद्रण विगत दो वर्ष से जिला स्तर पर करवाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु विभाग द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।
6. **बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स के रिक्त पदों की पूर्ति** – जैसा कि उपर के पैराज में बताया गया है कि ECI-NET पर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नियुक्त बीएलओ/सुपरवाइजर्स की सूची 31.08.2016 तक अपलोड की जानी है। जिला निर्वाचन

आधिकारियों से अनुरोध है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से चर्चा कर यह सुनिश्चित कर लें कि ईसीआई नेट पर उक्त सूचना निर्धारित दिनांक तक अपलोड कर दी गयी है। इस विषय में किसी प्रकार की लापरवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सूचनाएं SMS के माध्यम से बीएलओ/सुपरवाईजर्स को दी जाएगी, जिसके अनुसार उनको कार्य करने होंगे। अतः ECI-NET पर उक्त सूचना आवश्यक रूप से शुद्ध एवं सही सूचना उपलब्ध करवायी जाए।

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि बीएलओ के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करने हेतु सुपरवाईजर की व्यवस्था गत वर्ष से प्रारम्भ की गयी है जिसे प्रभावी रूप से क्रियाशील किया जाना है। आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम में सुपरवाईजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उनके अधीन आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों को नियमित रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा, ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ECI-NET पर इनको नियमानुसार निस्तारण कर उक्त आवेदन पत्रों का Status नियमित रूप से अपलोड करवा सकें।

#### 7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाईजर्स/बीएलओ का प्रशिक्षण –

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस इस वर्ष आयोजित किये जाने वाले इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के नये कार्य सम्पादित करने होंगे। इस हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ/सुपरवाईजर्स एवं जिले के मास्टर ट्रेनर्स को सघन रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम यथाशीघ्र अलग से आपको प्रेषित कर दिया जाएगा।

#### 8. स्वीप कार्यक्रम –

भारत निर्वाचन आयोग ने इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्वीप कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि प्रपत्र 1-8 में मतदाता सूचियों के आंकड़ों का विश्लेषण करवाकर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में विशेष प्रयास किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त जिलों का स्वीप कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न सरकारी विभागों, एनजीओ, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला इकाई, बैंक आदि का सहयोग लिया जाकर स्वीप कार्य योजना तैयार की जावे। जिलों की स्वीप कार्य योजना आवश्यक रूप से दिनांक 20 सितम्बर, 2016 तक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

#### 9. रिक्त पदों की सूचना –

जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि यदि जिले में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद रिक्त हैं तो इसकी सूचना

आवेल्मब विभाग को भेजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि सबाधेत विभागो से अनुरोध कर रिक्त पदों की यथाशीघ्र पूर्ति करवाई जा सके।

कृपया उक्त दिशा-निर्देश जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के ध्यान में अविलम्ब लाए जाए।

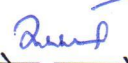
**10. कार्यक्रम की राजनैतिक दलों को जानकारी देना –**

संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम की जानकारी जिले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आवश्यक रूप से दी जाए। इस क्रम में उनके साथ जिला एवं ERO स्तर पर एक बैठक आयोजित कर उन्हें यथाशीघ्र प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध करें तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उनके सक्रिय सहयोग हेतु उन्हें आग्रह किया जाए एवं अभियान की विशेष तिथियों को बीएलए को मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर बीएलओ को सहयोग करने का आग्रह किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय में की जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार।**

भवदीया,

  
(राजेश यादव)

कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/

जयपुर, दिनांक

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –**

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारी गण , निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर कार्यक्रम अपलोड करने बाबत।
5. सांख्यिकी शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।



भारत निर्वाचन आयोग  
Election Commission of India

By e-mail/Speed-Post

निर्वाचन सदन  
NIRVACHAN SADAN  
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001  
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 23/2016-ERS (Vol.III)

To

The Chief Electoral Officers of  
All States and Union Territories.

Dated: 12<sup>th</sup> August, 2016

Subject:- Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2017 as qualifying date - Programme in all States/UTs except certain Assembly Constituencies of Andhra Pradesh and Telangana - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1<sup>st</sup> January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year) so that final publication of the electoral rolls could be made in the first week of January of the succeeding year. The revision schedule is prepared in such a manner that the electoral rolls are finally published well before National Voters' Day (25<sup>th</sup> January of every year) so that EPICs generated for new electors especially young voters (18-19 years) can be distributed to them in ceremonial manner on the day of NVD.

2 As the revision of electoral rolls actually starts with draft publication of electoral rolls, various pre-revision activities are required to be completed with the sole intention of achieving high fidelity electoral rolls. This year most of the pre-revision activities like Training and Orientation of EROs/AEROs, Appointment of Booth Level Officers (BLOs) and their Training and Orientation, Rationalization of Polling Stations, De-duplication campaign to remove duplicate entries in the electoral roll, Photography campaign for residual electors whose images are not available in the roll (H2H campaign to collect images of residual electors), Preparation of CEO's website for draft publication of integrated rolls and providing search facility, Standardization of search facility at website, updating of Control Tables (including polling stations updating) and database and integration of rolls (irrespective of whether it is election or non-election year), preparation of detailed action plan for SVEEP etc. have been included in the National Electoral Roll Purification (NERP) programme, and are currently going on in all the States/UTs. The NERP activities are to be completed by 15<sup>th</sup> September 2016 as per schedule of the programme already intimated vide letter No.23/2016(NERP)-ERS dated 14.07.2016. Needless to mention that any slippage in NERP targets/timelines would be seriously taken by Election Commission of India. It is further reiterated that the draft rolls shall have improved nazri naksha (digital on google map), (see NERP guidelines); the hand drawn map would not be acceptable to ECI.

Page 1 of 13

1/6

Tel : 011-23052205-18, Fax : 011-23052223-25, Website : www.eci.nic.in

"मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी"  
Greater Participation for a Stronger Democracy

3. The Commission has decided to take up revision of electoral rolls with reference to 1<sup>st</sup> January 2017 as the qualifying date. The revision shall be a Special Summary Revision in all States and Union Territories (Except the Assembly Constituencies of Andhra Pradesh and Telangana as per list attached) and shall be undertaken as per the schedule annexed to this letter, in accordance with the instructions contained in ERO's Handbook, 2012 along with subsequent instructions with regards to revision of electoral rolls /registration of electors, issued from time to time by the Commission.

4. Adequate publicity and awareness drive shall be ensured by DEOs & CEO regarding the summary revision programme. All the DEOs and CEO shall get the revision schedule properly disseminated to media, political parties and social organizations/RWAs and reach out to electors/eligible population extensively well before the date of draft publication of electoral rolls. For making the purpose of publication of draft rolls effective, series of SVEEP events, multiple and periodic meetings with political parties at Taluk, district and state levels and regular press meets may be organized. All DEOs and CEO shall separately call meetings of political parties and explain the schedule and seek cooperation expected of them before the date of draft publication. The draft publication should be done on the due date with fanfare and the copies of draft rolls should be handed over to political parties in public meeting in the presence of press, media and celebrities. In any case, proper acknowledgement receipt must be obtained and kept in record.

5. CEOs will request to the recognized political parties to appoint/identify a Booth Level Agent (BLA) for each polling booth/stations who would be associated with the Special Campaign for Roll Revision process on special campaign dates along with BLOs. On these Special Campaign dates, the BLO will go through the draft electoral roll with BLAs of recognized political parties of State concerned and identify the corrections, etc. It is pertinent to mention that BLAs once appointed from a recognized political party will continue as BLA, unless their appointment is rescinded /revoked by the political party concerned.

6. In addition to Divisional Commissioners, who shall act as Electoral Roll Observers for districts comprised within their Divisions, the Commission may depute its observers/ECI officers/roll auditors to randomly check, audit and supervise the revision process. Hence, it is absolutely essential that all roll related records should at all times be kept up to date and reports of progress as well as lists of the locations where field operations are in progress should be made available to them.

7. The electors' information in prescribed Formats 1-8 related to draft publication of the electoral roll shall be furnished by the Chief Electoral Officer along with his studied comments and explanatory memoranda to the Commission well before draft publication. Every DEO/ERO will do the similar study for his/her District/Assembly Constituency and forward the same to the CEO and also keep this ready for reference by Roll Observer/CEO.

8. The Chief Electoral Officer shall take prior written clearance of the Commission for final publication of the electoral rolls. A request to that effect shall be made to the Commission by the Chief Electoral Officer along with Formats 1-8 by 20<sup>th</sup> December, 2016 and with Formats 1-8, memoranda/note on how the roll revision process has achieved the targets fixed and the strategy to address any shortfalls during continuous updating may also be furnished. This should, in any case, be done at least 7 days before the date of final publication, so that clearance of the Commission may be conveyed at least 3 days before the date of final publication. CEOs may kindly take a note that non furnishing of this note would be seen with displeasing note by ECI.

9. It may be further noted that all communications and clarification relating to the revision should be addressed to the Pr. Secretary/Secretary (in charge of the State/UT) of ECI who will not only reply to the CEO concerned without any delay but also ensure that there is no slippage in the roll revision programme of the States under their charge. They will closely monitor the pre-revision activities and roll revision programme of their respective States/UTs so the CEOs must forward requisite report on progress of revision process at regular interval.

10. In order to facilitate the stakeholders and bringing more transparency in the process of electoral registration, the practice of computerization and posting of all application forms received in Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A on the website of the CEO on a day to day basis shall continue. The status of each application form should be clearly visible on each row of the list. Further, the web application used for this purpose should also provide a facility, that on clicking on any row in the list, the concerned application form can be printed by any citizen.

11. Periodic reporting to the Commission of progress made during the revision process in the prescribed Formats available at ECI dashboard shall also be done regularly and in accordance with the procedure laid down therein. The CEO must check it to ensure its status. At all DEOs/EROs do the necessary entries in the dash board for e-roll monitoring and in All India E-roll Monitoring Application (AERMA). The Commission has generally observed that there is avoidable laxity in this regard. It is reiterated and reiterated for absolute compliance by all that dash board has to be kept updated. If not then the concerned officer shall expose him/her to disciplinary actions.

12. With a view to ensure more involvement of political parties, the Commission has allowed BLAs of a recognized political parties to file applications in bulk, subject to the condition that a BLA shall not submit more than 10 Forms to BLO at one time/in one day. If a BLA files more than 30 Applications/Forms during entire period of filing claims and objections, then the cross verification must be done by ERO/AERO themselves. Further, the BLA will also submit a list of application forms with a declaration that he has personally verified the particulars of the application forms and is satisfied that they are correct.

3/1 The following guidelines are reiterated/prescribed for this exercise:-

13.

Display of list of claims and objections- (a) List of all claims and objections received should be put up on the website of CEO so that anybody including political parties and candidates are able to see this list and lodge objections with the concerned ERO. In addition to this -

i. Adequate publicity should be given by CEO to the fact that list of claims and objections is available on his/her website and objections can be raised before the EROs based on this list.

ii. CEO, all DEOs and all EROs should hold meetings with political parties and inform them about the publication of list of claims and objections on CEO's website and the latest instructions of the Commission about disposal of claims and objections.

iii. Political parties should be informed in writing by the CEO/DEO/ERO about publication of list of claims and objections on CEO's website.

iv. List of claims and objections should be made available by ERO to all political parties on weekly basis. For this purpose, the ERO should call a meeting of all political parties on regular interval and personally handover list of claims and objections to them and obtain acknowledgment. It is to be added that the list should be incremental instead of cumulative.

b. Decisions on Claims and Objections - Decision on claims and objections should be taken only after all of the following has been done -

i. At least seven clear days' period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following -

(1) Website of CEO as clickable lists for each polling station

(2) Notice board of ERO (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)

(3) Notice board of polling station (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)

(4) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.

ii. At least seven clear days have passed after ERO has given the list of claims and objections to political parties.

iii. All deletions which are done for reason of death shall be made only after ascertaining the facts to the satisfaction of ERO.

c. Verification before decisions on deletions -

i. All deletions except those which are done for reason of death of the elector should be verified by an officer not below the rank of Tehsildar before final order is passed on Form 7.

ii. All cases of deletions must be cross verified by an officer senior to the ERO if they fall in any of the following categories:-

- (1) Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters' list of the polling stations.
- (2) Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.
- iii. Cases of deletions except deletions by reason of death of the elector in which orders are passed by ERO, should be cross verified by supervisory officers in the following manner:-
  - (1) 2 % verification by Deputy DEO or equivalent officer.
  - (2) 1% verification by DEO.
  - (3) 0.5 % verification by Electoral Roll Observer.

d. Monitoring - Monitoring report in the prescribed format as available at Electoral Roll Monitoring Application at CEO's portal shall be updated periodically by the CEO/DEO/ERO as the case may be. CEO shall compile the report and send it to the Commission with his/her comments. The DEO/CEO shall make all efforts and shall personally ensure that data entry in All India E-Roll Monitoring Application in ECI portal through CEO's portal.

14. It is further clarified that NERP activities shall continue concurrently with revision. However, it must not cause any dislocation to roll revision activities which are statutory in nature. At the time of draft publication, the CEOs shall send a note on progress made in NERP activities till that time. In the publicity materials, both activities should be focused in an appropriate manner.

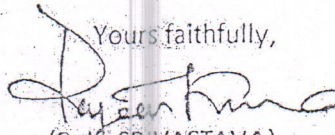
15. The CEO should write to all recognized national and state level political parties informing them the important points of the law and procedures of the revision and seek their cooperation in the roll revision exercise. A copy of letter issued to them may be endorsed to the Commission for record.

16. Preparation of Elector Photo Identity Card (EPIC) for those getting enrolled on the basis of becoming 18+ for the first time may be done latest by 20<sup>th</sup> January 2016 and be handed over to BLO/ERO/DEO etc by 22<sup>nd</sup> January 2016 for ceremonial distribution on 25th January 2016, the National Voters' Day.

17. The CEOs and all officers are further requested to extensively use the e-mail facility for prompt and accurate exchange of communication.

18. A copy of this letter should also be circulated to the DEOs/EROs in the State for taking immediate appropriate necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,  
  
(R. K. SRIVASTAVA)  
SENIOR PRINCIPAL SECRETARY.

Schedule for Special Summary Revision of Electoral rolls w.r.t. 1.1.2017 as the qualifying

(For Arunachal Pradesh<sup>1</sup>, Bihar<sup>2</sup>, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Uttarakhand<sup>3</sup>, Chandigarh<sup>4</sup> and NCT of Delhi<sup>5</sup>)

S.N	Stages of Revision	Period allowed for Stage
1	2	3
1.	Draft Publication of Electoral Rolls	01.10.2016 (Saturday)
2.	Period for filing of claims and objections	01.10.2016 (Saturday) to 31.10.2016 (Monday)
3.	Reading of relevant part/section of photo electoral rolls in Gram Sabha/Local Bodies and RWA meetings etc. and verification of names	07.10.2016 (Friday) and 14.10.2016 (Friday)
4.	Special Campaign dates with Booth Level Agents of political parties for receiving Claims and Objections	16.10.2016 (Sunday) and 23.10.2016 (Sunday)
5.	Disposal of Claims and Objections	By 30.11.2016 (Wednesday)
6.	Updating the database, merging of photographs, updating the Control Tables and preparation and printing of supplementary list	By 24.12.2016 (Saturday)
7.	Final Publication of Electoral Rolls	On 10.01.2017 (Tuesday)

<sup>1</sup> - In Arunachal Pradesh, dates for Special Campaign will be 9.10.2016 and 23.10.2016 and the date for final publication will be 11.01.2017.

<sup>2</sup> - For Bihar Special Campaign date will be 16.10.2016 and 23.10.2016.

<sup>3</sup> - Disposal of claims and objections will be done by 21.11.2016 in Uttarakhand.

<sup>4</sup> - Period of claims & Objections will be from 01.10.2016 to 27.10.2016 in Chandigarh.

<sup>5</sup> - Dates of special campaign will be 09.10.2016 and 23.10.2016 in Delhi.